जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

ऊर्जा राज्य मंत्री की पत्रकार वार्ता आयोजित
आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों को स्केल–3 पर सैद्धान्तिक सहमति

जयपुर, 19 जुलाई। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि पांचों विद्युत निगमों में कार्यरत आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों की प्रमुख मांग स्केल–3 देने पर सैद्धान्तिक सहमति बन गई है और इसे कब से और कैसे दिये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने गुरुवार को विद्युत भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से स्केल–3 देने के लिए राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ – बीएमएस द्वारा कई बार मांग पत्र दिए है और उनको स्वीकार करते हुए लम्बे समय से की जा रही मांग पर सकारात्मक रुप से विचार करते हुए सैद्धान्तिक सहमति बन गई है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने बताया कि पांचों विद्युत निगमों में लगभग 31 हजार तकनीकी कर्मचारी है और इनको स्केल–3 देने पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना करवाई जा रही है।

निजीकरण के सवाल पर बालते हुए श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी तक प्रदेश में केवल 4 शहरों को डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाईजी पर दिया गया है और दिसम्बर, 2018 तक निजीकरण का कोई नया माध्यम लागू नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ की 21 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुप से विचार किया जा रहा हैं और सरकार एवं विद्युत निगम प्रशासन के स्तर पर चर्चा कर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि पाचों विद्युत निगमों के अधिकारी–कर्मचारियों द्वारा टीम वर्क से किए गए कार्यों की वजह से ही विद्युत निगमों की स्थिति बेहतर हुई है।

राज्य सरकार तकनीकी कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राहत देना चाह रही है। इसलिये राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के पदाधिकारियों से अपील है कि आगामी 24 जुलाई को घोषित धरने को समाप्त कर दें और मांगों पर बैठकर बात करें।

पत्रकार वार्ता में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संजय मल्होत्रा और विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री आर.जी.गुप्ता भी उपस्थित रहे।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 783/2018